गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन की राशि में अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन से प्रभावित आदिवासियों को सुविधाओं का दिया जाना

3464. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद, आदिवासियों को उनकी आजीविका के लिये कोई अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है और वनोपज तथा वन विभाग द्वारा उन्हें दी जा रही मजदूरी भी उनके लिये कम होती जा रही है इसलिये क्या सरकार वनों में आदिवासियों की आजीविका के स्रोत जुटाने के लिये कोई उपाय करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन आदिवासियों को विस्तृत वन-क्षेत्र में हल्दी, पाईनएपल, टेपीयोका, अरबी, खरीफ, आलू आदि जैसी पेड़ों की छाया में पैदा हो सकने वाली फसलों और नीबू, संतरा आदि जैसे फलदार पेड़ों को लगाने की अनुमति दी जायेगी ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी): (क) और (ख) गैर-वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि को उपयोग में लाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। वन भूमि पर आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों को वन कार्य योजनाओं के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। वानिकी क्षेत्र में तीन स्कीमें आरम्भ की गई हैं जिनमें वर्ष 1988-89 के दौरान केवल आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किये जाने के लिये 885.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । (**नीचे देखिये**)

(ग) सरकारी वन भूमि में कृषि और बागवानी में संबंधित फसलों की खेती करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम	कुल परिव्यय	आदिवासी क्षेत्र हेतु निर्धारित निधियों की मात्रा	प्रतिशत
1.	वन चरागाह फार्मों की स्थापना	400.00	95.00	24
2.	ग्रामीण जलाऊ लकड़ी को पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी	1700.00	490.00	28
3.	हिमालय क्षेत्र में समन्वित मृदा और जल संरक्षण स्कीम	1200.00	300.00	25

वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाई गई बंजर भूमि

3465. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा कितनी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है;

(ख) क्या यह लक्ष्य के अनुरूप था; और

(ग) मध्य प्रदेश में बंजर भूमि में वृक्षारोपण के काम में तेजी लाने के लिये बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) वनी-

करण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष (1988-89) के दौरान वनीकरण का लक्ष्य 2 मिलियन हैक्टेयर है। जुलाई-सितम्बर के त्रैमास में किये गये कार्य के परिणाम नवम्बर, 1988 तक प्राप्त होंगे।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम जैसी परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में वर्तमान वर्ष के दौरान वनीकरण कार्यकलापों पर 18.07 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण और विकेन्द्रित जन पौधशालाओं की केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में वनीकरण के लिये वर्ष 1988-89 में 302 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है जबकि 1987-88 में यह राशि केवल 245 लाख रुपये थी।

Amendment in Criminal Procedure Code

@3466. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to amend Criminal Procedure Code for taking effective meausres in Matrimonial matters; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Aid from Aid India Consortium

3467. SHRI P. N. SUKUL:

SHRI BASUDEB MOHAPATRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the amount of aid pledged to India by the Aid India Consortium for the new fiscal year;

(b) whether it represents an increase or decrease over the aid provided by the Consortium last year;

(c) whether any special projects have been mentioned by the Consortium for the utilisation of its aid amount in the new fiscal year; and

(d) if so, what are the details of the projects to be financed out of the aid amount and the rate of interest to be charged thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The Aid India Consortium indicated total aid pledges of the order of US Dollar 6.3 billion in 1988-89 for India's development projects and programmes. This represents an increase of 16 per cent over the aid pledges of US Dollar 5.4 billion given last year.

(c) and (d) The details such as projects to be financed and the terms and conditions of such assistance are known as and when bilateral and multilateral aid negotiations are completed/finalised.

Sickness in the Jute Industry

3468. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that sickness in the jute industry is growing and that 65 per cent of the credit given to the industry may never be recovered; and

(b) if so, what steps Government are taking to revive the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) and (b) There was sickness in the jute industry. Of late, jute industry is improving its performance because of various measures taken by the Government such as:

@Previously Unstarred Question 2768, transferred from the 18th August, 1988.